उद्यमियों ने कहा, जमीन की कीमत कम हो जाए तो नैनी व बारा में खाली पड़ी जमीनों पर इकाइयों का जाल बिछ जाएगा

बेहतर बिजली के साथ कम दाम पर मिले जमीन तो उद्योग को लगेंगे पंख

1138 एकड़ में फैली है सरस्वती हाईटेक सिटी

50 प्रतिशत से अधिक जमीन खाली

10 हजार रुपये के करीब प्रति वर्गमीटर है जमीन

287 रुपये प्रति स्क्वायर गज जमीन देने की मांग

शहर की अपेक्षा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : यमुनापार का नैनी क्षेत्र। इसे उद्योग नगरी कहा जाता है। साथ ही बारा तहसील क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहीत की है। उद्यमियों को प्रत्येक सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई है। नैनी से सहसों तक बन रही रिंग रोड भी उद्यमियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इन सब के बावजूद यहां नए उद्यम उस तरह से नहीं लग पा रहे हैं, जैसी उम्मीद थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहां की जमीन की कीमत का अधिक होना है। इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा इस ओर सोच भी नहीं पा रहे हैं। वहीं, पुराने उद्यमी भी अपने कारोबार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उद्यमियों का मानना है कि जमीन की कीमत अगर कम हो जाए तो नैनी व बारा में खाली पड़ी जमीनों पर इकाइयों का जाल बिछ जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र स्थित 1138 एकड़ में फैली सरस्वती हाईटेक सिटी की करीब 50 प्रतिशत से अधिक जमीन खाली पड़ी है। इस पर उद्यम लगाने के लिए उद्यमी प्रयासरत है, लेकिन जमीन की कीमत रास्ते में बाधा बन रही है। करीब 10 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर यहां जमीन की कीमत है। जबकि उद्यमी जमीन का दाम कम करते हुए मप्र की तरह 287 रुपये प्रति स्क्वायर गज जमीन देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। उप्र राज्य औद्योगिक संघ के अध्यक्ष अरविंद राय का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र (नैनी) में सरस्वती हाईटेक सिटी में फैक्ट्री लगाने के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन की जरूरत होती है। वर्तमान में जमीन की करीब 10 हजार रुपये वर्ग मीटर कीमत है। इस रेट से एक एकड़ जमीन की कीमत लगभग सवा चार करोड़ रुपये होगी। जमीन खरीदने के लिए बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में उद्यमियों के सामने इतनी महंगी जमीन खरीदना आसान नहीं है। सरकार की मंशा स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की है। इसके लिए जमीन से लेकर इकाईयों को लगाने में भी राहत दी जानी चाहिए। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष संजय कुमार जैन का कहना है कि सरस्वती हाईटेक सिटी में जमीन की कीमत काफी अधिक है। प्रति स्क्वायर गज दस हजार रुपये जमीन दी जा रही है, जबकि कुछ ही किलोमीटर दूर पर मप्र की सीमा है। मप्र सरकार वहां 287 रुपये प्रति स्क्वायर गज जमीन दे रही है। ऐसे में इस ओर कदम उठाए जाने की जरूरत है। जमीन की कीमत कम होने से नए लघु उद्योग तेजी से स्थापित होंगे। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उपायुक्त उद्योग शरद टंडन का कहना है कि उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का सौंदर्यीकरण बेहद जरूरी : उद्यमियों की मानें तो औद्योगिक क्षेत्र में सौंदर्यीकरण बेहद जरूरी है। फायर स्टेशन के साथ ही अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। गेट लगने के साथ ही सीसीटीवी का जाल बिछना चाहिए। महिलाओं के लिए पिंक टायलेट व बस की व्यवस्था होनी चाहिए।

इलेक्ट्रिक, आटोमोबाइल व पैकेजिंग का बनेगा हब : बारा तहसील क्षेत्र में जनपद में दूसरा औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। यहां कई तरह की फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन सबसे अधिक जोर इलेक्ट्रिक, आटोमाबाइल, फूड प्रोसेसिंग, ब्रेवरेज, लेदर सामान, रेडीमेट गारमेंट, साइकिल मैंयुफैक्चरिंग, पैकेजिंग पर रहेगा।

सरस्वती हाईटेक सिटी

सोलर प्लांट व वेयर हाउसिंग का कारखाना

बीपीसीएल से खाली हुई जमीन यूपीसीडा को हस्तांतरित होने के बाद उस पर उद्योग लगाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सोलर प्लांट एवं वेयर हाउसिंग कारखाना स्तावित हैं। रेलवे का समर्पित मालभाड़ा गलियारा भी करछना स्टेशन पर प्रस्तावित है। ऐसे में जरूरी कच्चे माल एवं उत्पादों की ढुलाई की समस्या दूर हो जाएगी।

बिजली ट्रिपिंग की समस्या पूरी तरह से होनी चाहिए दूर

औद्योगिक क्षेत्र में बिजली ट्रिपिंग की समस्या बड़ी है। दिन में कई बार ट्रिपिंग होने से उद्यमियों का लाखों का नुकसान होता है। नैनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव नैय्यर का कहना है कि लगातार शिकायत करने के बाद बिजली ट्रिपिंग में सुधार तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो सका है। योजनाबद्ध तरीके से यहां बिजली समस्या का समाधान किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए यूपीसीडा द्वारा पावर कारपोरेशन को जमीन देनी चाहिए, ताकि उपकेंद्र का निर्माण हो सके।

इन बिंदुओं पर उद्यमियों का शुरू से रहा है जोर

- सिंगल विंडो एक्ट जल्द लागू हो।
- जमीनों के दाम कम किए जाएं।
- निवेश मित्रों को और सक्रिय किया जाए।
- औद्योगिक क्षेत्र की व्यवस्था यूपीसीडा बेहतर करे।
- सरस्वती हाईटेक सिटी में फ्लैटिंग फैक्ट्री बने।
- बिजली की ट्रिपिंग दूर की जाए।
- अग्निशमन केंद्र का निर्माण हो।
- गांवों में छोटे उद्यम लगाने वालों को एनओसी दी जाए।
- उद्यमियों को समय पर सब्सिडी मिले।